

नगर पालिका, पुसाद

बनाम

गोकलदास डोसा एंड कंपनी लिमिटेड

13 नवंबर, 1979

[आर.एस. सारकारिया और ओ.चिनाप्पा रेड्डी, जे.जे.]

भारत का संविधान 1950, अनुच्छेद 276(2), भारत सरकार अधिनियम 1935, धारा 142 ए(2), मध्य प्रांत और बरार नगर पालिका अधिनियम 1922, धारा 66(1)(बी) और व्यवसाय कर परिसीमा अधिनियम 1941, धारा 3 और अनुसूची का मद 4 -बोजा और बेल टैक्स -कपास ओटने और दबाने पर नगर पालिका द्वारा कर - संवैधानिक सीमा से अधिक सामान लगाने का जारी रहना - वैधता।

पुसाद जिला अकोला का हिस्सा था, जो चार हैदराबाद निर्दिष्ट जिलों में से एक था, जिसे बरार के नाम से जाना जाता था। ये जिले जो ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा प्रशासित थे, जिन्होंने बरार में लागू एक कानून बनाया, जिसे बरार नगरपालिका कानून, 1886 के रूप में जाना जाता है।

22 जनवरी, 1924 को गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल ने एक अधिसूचना जारी की जिसका प्रभाव यह हुआ कि बरार नगरपालिका कानून, 1886 को निरस्त कर दिया गया। और इसके स्थान पर मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 को बरार पर लागू किया गया। इसके अलावा, बरार नगरपालिका कानून के तहत लगाए गए करों को केंद्रीय प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 के तहत लगाया गया माना जाता था।

1 अगस्त, 1941 को सीपी और बरार विधानमंडल ने सीपी और बरार अधिनियम लागू किया जिसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 में "केंद्रीय प्रांत" शब्दों के बाद "और बरार" शब्द जोड़े गए।

इस बीच, भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा दी गई शक्ति के अनुसरण में डोमिनियन विधानमंडल द्वारा व्यवसाय कर परिसीमा अधिनियम, 1941 अधिनियमित किया गया था। और यह 1 अप्रैल, 1941 को लागू हुआ। इसमें प्रावधान था कि इसके प्रारंभ होने के बाद, नगर पालिकाएं 50/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक का कर नहीं लगाएंगी या वसूल नहीं करेंगी। हालाँकि, अधिनियम की अनुसूची के आइटम 4 के साथ पठित धारा 3 के अनुसार, सीपी नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 66(1)(बी) के तहत किसी पेशे, व्यापार या व्यवसाय के संबंध में नगर पालिका द्वारा लगाया गया कोई भी कर था। उपरोक्त सीमा से छूट दी गई है।

अपीलार्थी नगर पालिका, जिसे केंद्रीय प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1922 के तहत एक नगर समिति के रूप में गठित किया गया था, जिसने कपास को ओटने और दबाने पर उक्त अधिनियम की धारा 67, उप-धारा 5 और 7 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 66 (1) (बी) के तहत 9 जनवरी, 1932 की एक अधिसूचना द्वारा कर लगाया। इस कर को बोजा और बेल कर के नाम से जाना जाता था। इसने प्रतिवादी फर्म को उक्त कर के संबंध में एक मांग नोटिस और एक बिल जारी किया, जो नगर पालिका की सीमा के भीतर कपास ओटने और दबाने का व्यवसाय कर रहा था। प्रतिवादी की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया, उन्होंने एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय से यह घोषणा करने के लिए संपर्क किया कि उन पर लगाया गया बोजा और बेल टैक्स अधिकारातीत और असंवैधानिक है और मांग नोटिस को रद्द कर दिया जाए। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और मांग नोटिस को इस आधार पर

अपास्त कर दिया कि कर संविधान के अनुच्छेद 276 में निर्धारित 250/- रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा से अधिक था।

इस न्यायालय में अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि नगरपालिका समिति अकोट बनाम मणिलाल मानेकजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [1967] 2 एससीआर 100 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, बोजा और बेल टैक्स लगाया गया है। सी.पी. के तहत नगर पालिका अधिनियम, 1922, 1932 में, और किसी भी काल्पनिक कथा को आयात करने का कोई सवाल ही नहीं था, कर की मांग वैध थी।

अपील की स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. प्रश्नगत मांग नोटिस भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 142 ए(2) और संविधान के अनुच्छेद 276(2) का उल्लंघन नहीं करता है और वैध है। [15 ए]

2. नगरपालिका समिति, अकोट बनाम मणिलाल मानेकजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [1967] 2 एस.सी.आर. 100 में, इस न्यायालय ने माना कि व्यवसाय कर परिसीमा अधिनियम, 1941 की अनुसूची के मद 4 में 'लगाया गया' शब्द का अर्थ है कि जो कर लगाए जा सकते हैं, उन्हें उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले लगाया जाना चाहिए था। [14 डी]

3. यदि विचाराधीन कर वास्तव में 1941 अधिनियम के लागू होने से पहले, मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 66(1)(बी) के तहत लगाया गया था, यह व्यवसाय कर परिसीमा अधिनियम, 1941 की धारा 3 के साथ पठित मद 4 की छूट के अंतर्गत आएगा और संवैधानिक सीमा से अधिक इस तरह के अधिरोपण को

जारी रखना, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 142 ए(2) और संविधान के अनुच्छेद 276(2) के प्रावधानों के अनुरूप होगा। [14 ई-एफ]

मौजूदा मामले में, कर वास्तव में 1932 में सीपी नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 66(1)(बी) के तहत लगाया गया था। जब यह अधिनियम गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा जारी 22 जनवरी, 1924 की अधिसूचना के आधार पर बरार में लागू और लागू था। भले ही 1941 अधिनियम की धारा 3 और आइटम 4 को सख्ती से समझा जाए, लागू कर उपरोक्त आइटम 4 में अधिनियमित छूट के दायरे में आएगा। [13 डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 259/1970

बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) द्वारा विशेष सिविल आवेदन संख्या 329/67 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17-7-1968 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

एम. एन. फड़के और नौनीत लाल, अपीलार्थी की ओर से।

ए. जी. रत्नपर्खी, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

एम. एन. श्रॉफ, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से ।

एस. बी. सहारिया और वी. बी. सहारिया, हस्तक्षेपकर्ता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया -

सारकारिया, न्यायाधिपति.

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील बॉम्बे उच्च न्यायालय (नागपुर पीठ) डरा पारित निर्णय दिनांक 17 जुलाई, 1968 के खिलाफ निर्देशित है। यह इन तथ्यों से उत्पन्न होता है:

यहां अपीलार्थी, नगर परिषद, पुसाद को मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1922 के तहत एक नगर समिति के रूप में गठित किया गया था। इसके बाद, 9 जनवरी, 1932 को अपीलार्थी ने स्थानीय सरकार की मंजूरी से, सी.पी. नगर पालिका अधिनियम की धारा 66(1)(बी) के साथ धारा 67, उपधारा (5) और (7) के तहत बोजा टैक्स और बेल टैक्स के नाम से जाना जाने वाला कर कपास ओटने और दबाने पर लगाया। 392 पाउंड के प्रत्येक बोजा के लिए दर 2 अन्ना तय की गई थी। और 392 पाउंड की प्रत्येक गठरी के लिए 4 अन्नास। प्रतिवादी मेसर्स गोकुलदास डोसा एंड कंपनी लिमिटेड उक्त नगर पालिका की सीमा के भीतर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा कपास की जिनिंग और प्रेसिंग का व्यवसाय कर रहे थे। कर लगाने वाली 9 जनवरी, 1932 की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने 22 नवंबर, 1966 को वर्ष 1965-66 के लिए बोजा और बेल टैक्स के संबंध में 3,971.75 रुपये का डिमांड नोटिस और बिल जारी किया, जिसमें प्रतिवादी को कर की वह राशि भुगतान करने की आवश्यकता थी। प्रतिवादियों ने 28 मार्च, 1967 को इस मांग पर आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं। 7 अप्रैल, 1967 को अपीलार्थी द्वारा आपत्तियों को खारिज कर दिया गया।

व्यथित होकर, प्रतिवादियों ने 9 अप्रैल, 1967 को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि उन पर लगाया गया बोजा और बेल टैक्स अधिकारातीत और असंवैधानिक है। उन्होंने प्रार्थना की कि बेल और डिमांड नोटिस को अपास्त कर दिया जाए। उन्होंने आगे अपीलकर्ता के खिलाफ निषेधाज्ञा रिट जारी करने का दावा किया, जो उसे संविधान

के अनुच्छेद 276 में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक प्रतिवादी से कर वसूलने से रोके।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29 अप्रैल, 1967 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से कर की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद, अपील के तहत अपने फैसले से, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और डिमांड नोटिस को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि कर संविधान के अनुच्छेद 276 में तय की गई 250 रुपये प्रति वर्ष की सीमा से अधिक थी।

उच्च न्यायालय ने, जो वह कहता है, उस न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए "निर्णयों की एक श्रृंखला" का पालन करने का इरादा रखते हुए माना है कि बेल और बोजा कर के माध्यम से मांग संविधान के अनुच्छेद 276 में निर्धारित सीमा से अधिक है। अवैध है। इसलिए, उसने संबंधित मांग नोटिस को अपास्त कर दिया। जब उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के "निर्णयों की एक श्रृंखला" के बारे में बात की, तो संभवतः उसके मन में इस न्यायालय के दो निर्णय थे, अर्थात्: नगर पालिका समिति, अकोट बनाम मणिलाल मानेकजी प्रा. लिमिटेड और अन्य <sup>(1)</sup> और बल्लभदास मथुरादास लखानी और अन्य बनाम नगरपालिका समिति, मलकापुर <sup>(2)</sup> ।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री एम.एन.फडके का कहना है कि तथ्यों के आधार पर, इस न्यायालय के उपरोक्त दो निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। अधिवक्ता के मुताबिक, ठीक से पढ़ें तो ये फैसले उनकी इस दलील का समर्थन करते हैं कि अपीलार्थी की बोजा और बेल टैक्स की मांग वैध है। यह बताया गया है कि जिस कर से यह न्यायालय नगरपालिका समिति, अकोट के मामले में चिंतित था, वह पुराने नगरपालिका कानून के तहत लगाया गया कर था, जिसे पर सी.पी. नगर पालिका अधिनियम, 1922 के तहत 27 जनवरी, 1924 की अधिसूचना द्वारा लगाया गया माना

गया था; यह इस आधार पर था कि व्यवसाय कर परिसीमा अधिनियम, 1941 की अनुसूची के मद 4 को सख्ती से अत्यान्वयन करते हुए, इस न्यायालय ने माना कि केवल सी.पी. नगर पालिका अधिनियम, 1922 के तहत लगाए गए कर और वे नहीं जिन्हें उस अधिनियम के तहत कल्पना के आधार पर लगाया गया माना जाता है, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुच्छेद 142 ए (2) और संविधान के अनुच्छेद 276 में सम्बंधित खंड द्वारा बचाए गए थे। इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि, मौजूदा मामले में, कर 1932 में सी.पी. नगर पालिका अधिनियम, 1922 के तहत लगाया गया था, और किसी भी काल्पनिक कथा को आयात करने का कोई सवाल ही नहीं था।

इसके विपरीत, श्री रत्नापारखी का मानना है कि विचाराधीन अधिरोपण सीधे तौर पर नगरपालिका समिति अकोट के मामले (वही) के अनुपात से प्रभावित हुआ था। इसके अलावा, यह पहली बार आधे-अधूरे मन से प्रस्तुत किया गया है कि पुराने कानून के तहत भी, नगरपालिका समिति व्यवसायों पर केवल 500 रुपये प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक कर लगा सकती है।

सबसे पहले श्री रत्नापारखी के अंतिम तर्क पर गौर करें तो हमें इसमें कोई दम नजर नहीं आता। सी.पी. नगर पालिका अधिनियम, 1922, नगर पालिका द्वारा लगाए जाने वाले व्यवसायों पर व्यवसाय कर की कोई सीमा तय नहीं करता है। इसलिए, हमें इस तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

आगे बढ़ने से पहले, मुद्दे से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की जानकारी होना जरूरी है।

पुसाद जिला अकोला का एक हिस्सा था, जो चार हैदराबाद निर्दिष्ट जिलों में से एक था, जिसे बरार के नाम से जाना जाता था। वे जिले ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन 1904 के भारत (विदेशी क्षेत्राधिकार) ऑर्डर-इन-काउंसिल के तहत गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा प्रशासित थे। उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गवर्नर-

जनरल-इन-काउंसिल ने बरार में लागू एक कानून बनाया, जिसे बरार नगरपालिका कानून, 1886 के नाम से जाना जाता है। जिसने बरार में कार्यरत नगर पालिकाओं को व्यावसायिक कर लगाने में सक्षम बनाया। 22 जनवरी, 1924 को गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल ने एक अधिसूचना जारी की, जो हमारे उद्देश्य के लिए सामग्री के रूप में इस प्रकार थी:

"नंबर 58-1.- भारतीय (विदेशी क्षेत्राधिकार) ऑर्डर-इन-काउंसिल, 1902 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में उसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार के विदेश विभाग संख्या 8510-आईबी, दिनांक 3 नवंबर, 1913 की अधिसूचना की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, बरार के लिए कुछ अधिनियमों को लागू करते हुए, अर्थात्:-

प्रविष्टि संख्या 149 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि डाली जाएगी:-

150. मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 (1922 का द्वितीय) (1) धारा 2 में:-

(ए) उप-धारा (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) बरार नगरपालिका कानून, 1886, को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।"



(बी) उप-धारा (2) में, शब्द "अधिनियम" के स्थान पर "कानून" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

इस अधिसूचना का प्रभाव यह हुआ कि बरार नगरपालिका कानून, 1886 को निरस्त कर दिया गया और मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 को बरार पर लागू कर दिया गया; और इसके अलावा, बरार नगर कानून के तहत लगाए गए करों को केंद्रीय प्रांत नगर पालिका अधिनियम के तहत लगाया या मूल्यांकन किया गया माना जाता था।

इसके बाद 9 जनवरी, 1932 को सी.पी. नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 66(1)(बी) के तहत बोजा और बेल टैक्स लगाने की एक अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के आधार पर विवादित मांग नोटिस जारी किया गया था। यह कर मध्य प्रांत में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू हो गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 142 ए(2) निम्नानुसार प्रदान करती है:

"142 ए(2).- प्रांत को किसी एक व्यक्ति के संबंध में देय कुल राशि या किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड को, या प्रांत में अन्य स्थानीय प्राधिकारी व्यवसायों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर करों के माध्यम से मार्च के इकतीसवें दिन, उन्नीस सौ उन्तीस के बाद, प्रति वर्ष पचास रुपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते, यदि उस तिथि को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रांत या ऐसी किसी नगर पालिका, बोर्ड या प्राधिकरण के मामले में व्यवसायों, व्यापारों, आजीविका या रोजगार पर कर लागू था दर, या

अधिकतम दर, जो प्रति वर्ष पचास रुपये से अधिक हो, इस उपधारा के पूर्ववर्ती प्रावधान, जब तक कि कुछ समय के लिए डोमिनियन विधानमंडल के कानून द्वारा इसके विपरीत प्रावधान न किया गया हो, उस प्रांत, नगर पालिका, बोर्ड या प्राधिकरण के संबंध में प्रभाव पड़ता है मानो पचास रुपये प्रति वर्ष के संदर्भ के स्थान पर उस दर या अधिकतम दर, या ऐसी निचली दर, यदि कोई हो (पचास रुपये प्रति वर्ष से अधिक दर होने पर) का संदर्भ प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। जैसा कि फिलहाल डोमिनियन विधानमंडल के कानून द्वारा तय किया जा सकता है; और डोमिनियन विधानमंडल का कोई भी कानून इस प्रावधान के किसी भी उद्देश्य के लिए बनाया गया है या तो आम तौर पर या किसी विशिष्ट प्रांत, नगर पालिकाओं, बोर्डों या प्राधिकरणों के संबंध में बनाया जा सकता है।”

भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसरण में, डोमिनियन विधानमंडल ने व्यवसाय कर परिसीमा अधिनियम, 1941 अधिनियमित किया। जो 1 अप्रैल 1941 को लागू हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि उस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, नगर पालिकाएँ प्रति वर्ष 50/- रुपये से अधिक का कर नहीं लगाएंगी या वसूल नहीं करेंगी। हालाँकि, इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा, इसकी अनुसूची में निर्दिष्ट करों को इस सीमा से छूट दी गई थी। अनुसूची का मद 4 इस प्रकार है:

"सीपी नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 1 के खंड (बी) या धारा 66 के तहत नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर किसी भी पेशे

को अपनाने या व्यापार करने या व्यवसाय करने वाले व्यक्ति पर कर लगाया जाता है।"

1 अगस्त 1941 को सी.पी. और बरार विधानमंडल ने अधिनियम 15 ऑफ 1941 अधिनियमित किया जिसे सी.पी. और बरार अधिनियम कहा जाता है। जिसके परिणामस्वरूप, "मध्य प्रांत" शब्दों के बाद "और बरार" शब्द जोड़े गए। मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 में जहां भी घटित होता है।

धारा 142 ए(2) परंतुक के अनुरूप एक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 276(2) के परंतुक में पाया जाना है, जो इस प्रकार है:

"बशर्ते कि यदि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में किसी भी राज्य या ऐसी किसी नगर पालिका, बोर्ड या प्राधिकरण के मामले में पेशे, व्यापार, आजीविका या रोजगार पर कर लागू था दर, या अधिकतम दर, जो प्रति वर्ष दो सौ पचास रुपये से अधिक हो, ऐसा कर तब तक लगाया जा सकता है जब तक कि इसके विपरीत प्रावधान संसद द्वारा कानून द्वारा नहीं किया जाता है, और संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या तो आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट राज्यों, नगर पालिकाओं बोर्डों या प्राधिकरणों के संबंध में हो सकता है।"

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य से यह देखा जाएगा कि उस अधिनियम की धारा 2 द्वारा लगाई गई सीमा से व्यवसाय कर परीसीमा अधिनियम, 1941 (संक्षेप में 1941 अधिनियम) की अनुसूची में मद 4 के तहत छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, प्रश्नगत कर डोमिनियन विधानमंडल द्वारा पारित 1941 अधिनियम से पहले सी.पी. नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 66 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत भारत सरकार

अधिनियम, 1935 की धारा 142 ए(2) के परंतुक के प्राप्त शक्ति के आधार पर लागू हुआ। यह शर्त आक्षेपित कर से पूरी हो गई है। यह कर वास्तव में 1922 के उक्त अधिनियम की धारा 66(1)(बी) के तहत 1932 में लगाया गया था, जब यह अधिनियम बरार में गवर्नर-जनरल द्वारा जारी 22 जनवरी 1924 की अधिसूचना के आधार पर लागू किया गया था। इस प्रकार, भले ही 1941 अधिनियम की धारा 3 और मद 4 का कड़ाई से अर्थ लगाया जाए, विवादित कर पूरी तरह से उपरोक्त मद 4 में अधिनियमित छूट के दायरे में आएगा।

अब, आइए नगरपालिका समिति अकोट के मामले (वही) पर ध्यान दें जिस पर संभवतः उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था। वर्तमान में यह देखा जाएगा कि यदि इस निर्णय को ठीक से पढ़ा जाए तो यह अपील के तहत निर्णय का समर्थन नहीं करता है। उस मामले में, विवादित कर वास्तव में 1941 के अधिनियम के लागू होने के बाद, 1922 के सी.पी. नगर पालिका अधिनियम के तहत, नगरपालिका समिति द्वारा नहीं लगाया गया था। लेकिन 14 मार्च 1899 की एक अधिसूचना संख्या 98 के तहत लगाया गया था। अपीलार्थी नगर पालिका समिति की ओर से तर्क यह था कि चूंकि 1899 की यह अधिसूचना केंद्रीय प्रांत और बरार नगर पालिका अधिनियम, 1922 (जिसने केवल सी.पी. नगर पालिका अधिनियम 1922 का नाम बदल दिया है) के तहत जारी की गई मानी जाएगी, यह 1922 के सी.पी. नगर पालिका अधिनियम की धारा 66(1)(बी) के तहत 'लगाया गया' कर 1941 अधिनियम की अनुसूची के आइटम 4 के चिंतन के अंतर्गत होगा। न्यायालय की ओर से बोलते हुए सीकरी, न्यायाधिपति ने इस विवाद को इन शब्दों में खारिज कर दिया:

"हमारी राय में उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा। सबसे पहले,

आइटम नंबर 4 व्यवसाय कर सीमा अधिनियम, 1941 की धारा 2

द्वारा लगाई गई सीमा से छूट है। और छूट को सख्ती से समझा जाना चाहिए। दूसरे, अनुसूची की धारा 3 और मद 4 का प्रभाव कर की उद्ग्रहणशीलता को जारी रखना है और, हमारी राय में, इस मद को कड़ाई से एक कर कानून की तरह समझा जाना चाहिए। यदि श्री गुप्ता हमें यह विश्वास दिलाने में सफल रहे होते कि यदि यह व्याख्या की गई तो विषय निरर्थक हो जाएगा, उसके पक्ष में कहने को कुछ होगा। लेकिन मद ओटिओस नहीं होगा, भले ही हम मद 4 को गलत विवरण का मामला न मानें लेकिन स्पष्ट अर्थ बताएं कि मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 का अर्थ मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 है, न कि मध्य प्रांत और बरार नगर पालिका अधिनियम, 1922। मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 66(1)(बी) के तहत जारी अधिसूचनाओं के आधार पर मध्य प्रांत में नगर पालिकाओं द्वारा विभिन्न कर लगाए गए होंगे। और वे मद 4 के दायरे में आएंगे...

"थोपा गया" शब्द.... हमारे विचार में, इसका मतलब है कि जो कर लगाए जा सकते हैं, वे व्यवसाय कर सीमा अधिनियम, 1941 के लागू होने से पहले लगाए गए होने चाहिए। यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 142 ए(2) के अनुरूप है।"

महत्वपूर्ण शब्द वे हैं जिन्हें रेखांकित किया गया है। ये शब्द स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यदि प्रश्नगत कर, वास्तव में, 1941 अधिनियम के लागू होने से पहले, मध्य प्रांत नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 66(1)(बी) के तहत लगाया गया था, तो यह व्यवसाय कर परीसीमा अधिनियम, 1941 की धारा 3 के साथ पठित मद 4 की छूट के

अंतर्गत आएगा, और संवैधानिक सीमा से अधिक इस तरह के अधिरोपण को जारी रखना, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 142 ए(2) और संविधान के अनुच्छेद 276(2) के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

चूंकि तत्काल मामले में, प्रश्नगत कर 1932 में सी.पी. नगर पालिका अधिनियम, 1922 की धारा 66(1)(बी) के तहत लगाया गया था, 1941 अधिनियम लागू होने से बहुत पहले, और इसमें किसी भी प्रकार की कल्पना, काल्पनिकता को शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं है, वास्तव में नगरपालिका समिति अकोट के मामले का अनुपात, अपीलकर्ता-नगर परिषद के तर्क का समर्थन करता है, और उच्च न्यायालय के फैसले में त्रुटि को उजागर करता है।

बल्लभदास मथुरादास लखानी एवं अन्य बनाम नगर पालिका समिति, मलकापुर (वही) मामले पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह सीधे तौर पर नगर समिति, अकोट बनाम मणिलाल मानेकजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (वही) के अनुपात का अनुसरण करता है।

ऊपर कही गई सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि विचाराधीन मांग नोटिस भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 142 ए(2) और संविधान के अनुच्छेद 276(2) का उल्लंघन नहीं करता है, और वैध है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं और प्रतिवादी की रिट याचिका को खारिज करते हैं और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

एनवीके

अपील स्वीकार की गई।

- (1) [1967] 2 एस.सी.आर 100
- (2) ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1002.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

**अस्वीकरण-** इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

\*\*\*\*\*